

## अनुसूचित जनजाति समाज में लैंगिक असमानता: सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का सैद्धांतिक एवं साहित्यिक विश्लेषण

**Kundan Gathe**

Research Scholar, Department of Sociology , Malwanchal University, Indore

**Dr. Sonali Pandit**

Supervisor, Department of Sociology , Malwanchal University, Indore

### **सारांश**

यह शोध-पत्र अनुसूचित जनजाति समाज में विद्यमान लैंगिक असमानता के सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का सैद्धांतिक एवं साहित्यिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि जनजातीय समाज को प्रायः समानतावादी माना जाता है, तथापि वास्तविकता में महिलाओं की स्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संपत्ति अधिकार तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में अपेक्षाकृत कमजोर पाई जाती है। सामाजिक मान्यताएँ, परंपरागत भूमिकाएँ, संसाधनों तक सीमित पहुँच तथा गरीबी जैसे कारक इस असमानता को और गहरा करते हैं। साथ ही, वैश्वीकरण, शिक्षा के प्रसार एवं सरकारी योजनाओं के प्रभाव से कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी दृष्टिगत होते हैं। यह अध्ययन विभिन्न सिद्धांतों एवं पूर्व शोधों के आधार पर लैंगिक असमानता की प्रकृति, कारणों एवं परिवर्तनों को समझने का प्रयास करता है तथा नीति-निर्माण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोगी दिशा प्रदान करता है।

**मुख्य शब्द:** लैंगिक असमानता, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, महिला सशक्तिकरण

### **प्रस्तावना**

भारतीय समाज अपनी बहुलतावादी संरचना, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक स्तरीकरण के लिए जाना जाता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति समाज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह समाज अपनी विशिष्ट जीवन-शैली, परंपराओं, आजीविका के साधनों और सामुदायिक संरचनाओं के कारण मुख्यधारा से भिन्न पहचान बनाए रखता है। सामान्यतः यह धारणा प्रचलित रही है कि जनजातीय समाज अपेक्षाकृत अधिक समानतावादी होता है, जहाँ स्त्री और पुरुष के बीच संबंधों में संतुलन पाया जाता है। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि लैंगिक असमानता के विभिन्न रूप यहाँ भी विद्यमान हैं, जो सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से गहराई से प्रभावित होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, संपत्ति पर अधिकार तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की स्थिति अक्सर पुरुषों की अपेक्षा कमजोर पाई जाती है, जिससे उनके सामाजिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न होती है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत परंपरागत मान्यताएँ, सांस्कृतिक धारणाएँ तथा लैंगिक भूमिकाओं का निर्धारण महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है, वहीं आर्थिक कारकों जैसे गरीबी, संसाधनों तक सीमित पहुँच, श्रम विभाजन और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होने की प्रवृत्ति भी असमानता को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा का प्रसार तथा सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के प्रभाव से जनजातीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाएँ भी देखने को मिल रही हैं, जिनका प्रभाव लैंगिक

संबंधों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है। इस संदर्भ में लैंगिक असमानता को केवल एक सामाजिक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक घटना के रूप में समझना आवश्यक हो जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समाज में लैंगिक असमानता के सामाजिक एवं आर्थिक आयामों का सैद्धांतिक एवं साहित्यिक विश्लेषण प्रस्तुत करना है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि किन कारकों के कारण यह असमानता उत्पन्न होती है और समय के साथ इसमें किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। यह अध्ययन न केवल समाजशास्त्रीय विमर्श को समृद्ध करेगा, बल्कि नीति-निर्माण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

### **अध्ययन की पृष्ठभूमि**

भारत का सामाजिक ढांचा विविधताओं से युक्त है, जिसमें अनुसूचित जनजाति समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं के कारण विशेष महत्व रखता है। परंपरागत रूप से यह माना जाता रहा है कि जनजातीय समाज अपेक्षाकृत अधिक समानतावादी होता है, किंतु वास्तविकता में यहाँ भी लैंगिक असमानता विभिन्न रूपों में विद्यमान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में सीमित पाई जाती है। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, श्रम विभाजन तथा पारिवारिक दायित्वों का असमान वितरण महिलाओं की स्थिति को और जटिल बनाता है। वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव से इन असमानताओं में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं, किंतु इनके स्वरूप एवं तीव्रता में क्षेत्रीय विविधताएँ स्पष्ट हैं। विशेष रूप से मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में निवासरत जनजातीय समुदायों के संदर्भ में यह अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के अंतर्गत लैंगिक असमानता की प्रकृति तथा उसके परिवर्तनों को समझने का प्रयास करता है।

### **अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व**

अनुसूचित जनजाति समाज में लैंगिक असमानता का अध्ययन समकालीन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए अत्यंत आवश्यक एवं प्रासंगिक विषय है, क्योंकि यह न केवल सामाजिक न्याय के प्रश्नों से जुड़ा है बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि सामान्यतः यह धारणा प्रचलित है कि जनजातीय समाज अपेक्षाकृत समानतावादी होता है, तथापि वास्तविक स्थिति में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसरों तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों जैसे मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में यह असमानता अधिक जटिल रूप में दिखाई देती है, जहाँ पारंपरिक मान्यताएँ, सीमित संसाधन एवं जागरूकता का अभाव महिलाओं की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है कि वर्तमान में लागू विभिन्न सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों तथा गैर-सरकारी प्रयासों के वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा सके और यह समझा जा सके कि ये पहलें किस हद तक लैंगिक असमानता को कम करने में सफल रही हैं। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के अंतर्संबंधों को स्पष्ट करते हुए नीतिगत निर्माण, योजना क्रियान्वयन तथा स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश प्रदान करेगा, जिससे जनजातीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सके और समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

### **अनुसूचित जनजाति की संकल्पना एवं परिभाषा**

भारतीय संदर्भ में "अनुसूचित जनजाति" (Scheduled Tribes) उन समुदायों को संदर्भित करता है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विशेष रूप से अधिसूचित किया गया है। ये समुदाय अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक अलगाव, पारंपरिक जीवन-शैली, तथा आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अन्य वर्गों से भिन्न माने जाते हैं। जनजातियों की पहचान के लिए सामान्यतः कुछ प्रमुख मानदंड स्वीकार किए जाते हैं, जैसे—आदिम विशेषताएँ, विशिष्ट संस्कृति, सीमित बाहरी संपर्क, भौगोलिक पृथकता, तथा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन। समाजशास्त्रियों जैसे जी.एस. घुर्ये एवं वेरियर एल्विन ने जनजातीय समाज को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है, जो सामुदायिक जीवन, परंपरागत मान्यताओं, तथा प्रकृति-आधारित आजीविका पर निर्भर होते हैं।

अनुसूचित जनजातियाँ प्रायः जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं और उनका जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। इन समुदायों की सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत सरल होती है, जिसमें कुटुंब, कबीला और गोत्र जैसी इकाइयाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, औपनिवेशिक काल और आधुनिक विकास प्रक्रियाओं के प्रभाव से इनकी पारंपरिक संरचनाओं में परिवर्तन आया है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और आजीविका पर भी प्रभाव पड़ा है। संविधान द्वारा इन्हें विशेष संरक्षण, आरक्षण, तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है, ताकि इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, अनुसूचित जनजाति की संकल्पना केवल एक प्रशासनिक श्रेणी नहीं, बल्कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक इकाई के रूप में समझी जानी चाहिए।

### **भारत में जनजातीय समाज की विशेषताएँ**

भारत में जनजातीय समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं के कारण अन्य सामाजिक समूहों से अलग पहचान रखता है। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता उनकी प्रकृति-आधारित जीवन-शैली है, जिसमें आजीविका के लिए वन, जल एवं भूमि संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता होती है। जनजातीय समुदाय सामान्यतः दूरस्थ, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिससे उनका मुख्यधारा के समाज से अपेक्षाकृत सीमित संपर्क बना रहता है। सामाजिक संरचना की दृष्टि से यह समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित होता है, जहाँ गोत्र, कुल एवं वंश संबंधों का विशेष महत्व होता है और सामुदायिक जीवन की भावना प्रबल होती है।

सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातीय समाज अत्यंत समृद्ध होता है, जिसमें अपनी विशिष्ट भाषा, लोक-परंपराएँ, रीति-रिवाज, नृत्य, संगीत एवं धार्मिक मान्यताएँ शामिल होती हैं। इनकी धार्मिक आस्थाएँ प्रायः प्रकृति-पूजा, पूर्वज-पूजा एवं आत्मवाद (Animism) पर आधारित होती हैं। सामाजिक संबंधों में समानता एवं सहयोग की भावना दिखाई देती है, हालांकि आधुनिक प्रभावों के कारण कुछ स्थानों पर असमानताएँ भी उभर रही हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समाज मुख्यतः निर्वाह अर्थव्यवस्था (subsistence economy) पर आधारित होता है, जिसमें कृषि, शिकार, संग्रहण, पशुपालन एवं लघु वन उत्पादों का संग्रह प्रमुख होते हैं।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनजातीय समाज अपेक्षाकृत पिछड़ा रहा है, जिसका कारण भौगोलिक अलगाव, संसाधनों की कमी एवं जागरूकता का अभाव है। इसके अतिरिक्त, बाहरी हस्तक्षेप, औद्योगिकीकरण एवं विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसी समस्याएँ

भी सामने आई हैं। बावजूद इसके, जनजातीय समाज में सामुदायिक एकता, पारस्परिक सहयोग एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जैसी सकारात्मक विशेषताएँ विद्यमान हैं। इस प्रकार, भारत का जनजातीय समाज विविधता, परंपरा एवं परिवर्तन का एक जटिल किन्तु महत्वपूर्ण सामाजिक स्वरूप प्रस्तुत करता है।

### **जनजातीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति**

जनजातीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति भारतीय समाज की बहुलतावादी प्रकृति का एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करती है। जनजातीय समाज की सामाजिक संरचना मुख्यतः कबीलाई (tribal) व्यवस्था पर आधारित होती है, जिसमें परिवार, कुटुंब, कुल (clan) और गोत्र प्रमुख इकाइयाँ होती हैं। यह संरचना सामुदायिक जीवन, पारस्परिक सहयोग तथा समानता के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जहाँ सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत सरल, अनौपचारिक और प्रत्यक्ष होते हैं। परिवार प्रायः पितृसत्तात्मक होता है, किंतु कुछ जनजातियों में मातृसत्तात्मक प्रवृत्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। विवाह संस्था में भी विशिष्टता पाई जाती है, जैसे—कुल या गोत्र के बाहर विवाह (exogamy), वधू मूल्य (bride price) की प्रथा, तथा सामुदायिक स्वीकृति का महत्व।

संस्कृतिक दृष्टि से जनजातीय समाज अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण होता है, जिसमें लोक-परंपराएँ, रीति-रिवाज, भाषा, नृत्य, संगीत और कला के विभिन्न रूप शामिल होते हैं। इनकी संस्कृति का गहरा संबंध प्रकृति से होता है, जिसके कारण प्रकृति-पूजा, पूर्वज-पूजा तथा आत्मवाद (Animism) प्रमुख धार्मिक विश्वासों के रूप में विद्यमान हैं। त्योहार, अनुष्ठान और सामुदायिक आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आर्थिक गतिविधियाँ भी सामाजिक संरचना से गहराई से जुड़ी होती हैं, जहाँ श्रम का विभाजन प्रायः आयु और लिंग के आधार पर निर्धारित होता है, हालांकि यह विभाजन कठोर न होकर लचीला होता है। आधुनिकता, शिक्षा, शहरीकरण एवं सरकारी हस्तक्षेप के प्रभाव से जनजातीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तन की प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे पारंपरिक मूल्यों और नई प्रवृत्तियों के बीच संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार, जनजातीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति एक गतिशील प्रणाली है, जो परंपरा और परिवर्तन दोनों को समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखती है।

### **लैंगिक असमानता: सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य**

#### **1. लैंगिक असमानता की संकल्पना**

लैंगिक असमानता से आशय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों, अवसरों, संसाधनों तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के असमान वितरण से है। यह केवल जैविक भिन्नताओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मान्यताओं और संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्मित एवं पुनरुत्पादित होती है। जनजातीय समाज में इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय-निर्माण में असमान हिस्सेदारी के रूप में देखा जा सकता है।

#### **2. लैंगिक भूमिकाएँ एवं सामाजिक निर्माण**

लैंगिक भूमिकाएँ समाज द्वारा निर्धारित अपेक्षाएँ होती हैं, जो स्त्री और पुरुष के व्यवहार, कार्य एवं जिम्मेदारियों को परिभाषित करती हैं। ये भूमिकाएँ जन्मजात नहीं होतीं, बल्कि समाजीकरण (socialization) की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। जनजातीय समाज में भी पारंपरिक

मान्यताएँ महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित करती हैं, जबकि पुरुषों को बाहरी एवं निर्णयात्मक भूमिकाएँ दी जाती हैं, जिससे असमानता को संस्थागत आधार मिलता है।

### 3. नारीवादी सिद्धांत

नारीवादी दृष्टिकोण लैंगिक असमानता को समझने का प्रमुख सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। उदारवादी नारीवाद (Liberal Feminism) समान अधिकारों एवं अवसरों पर बल देता है, जबकि उग्रवादी नारीवाद (Radical Feminism) पितृसत्तात्मक संरचनाओं को असमानता का मूल कारण मानता है। समाजवादी नारीवाद (Socialist Feminism) आर्थिक शोषण और वर्ग संबंधों के साथ लैंगिक असमानता को जोड़कर देखता है। ये सभी दृष्टिकोण जनजातीय महिलाओं की स्थिति को समझने में सहायक हैं।

### 4. संरचनात्मक-कार्यात्मकतावाद

यह सिद्धांत समाज को एक संगठित प्रणाली के रूप में देखता है, जहाँ प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट कार्य होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लैंगिक भूमिकाएँ सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। हालांकि, यह दृष्टिकोण अक्सर असमानताओं को स्वाभाविक एवं आवश्यक मानकर उन्हें वैधता प्रदान करता है, जिससे लैंगिक असमानता की आलोचना सीमित हो जाती है।

### 5. संघर्ष सिद्धांत

संघर्ष सिद्धांत के अनुसार समाज में संसाधनों और शक्ति के असमान वितरण के कारण विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। यह दृष्टिकोण लैंगिक असमानता को पुरुषों द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण एवं प्रभुत्व के परिणाम के रूप में देखता है। जनजातीय समाज में भी आर्थिक संसाधनों और निर्णय-निर्माण की शक्ति पर पुरुषों का अधिक नियंत्रण इस असमानता को बनाए रखता है।

### 6. अंतर्विभाजन (Intersectionality) का दृष्टिकोण

अंतर्विभाजन का सिद्धांत यह बताता है कि लैंगिक असमानता केवल लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि जाति, वर्ग, जनजातीय पहचान, क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक कारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। जनजातीय महिलाओं के संदर्भ में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे एक साथ कई प्रकार के वंचनाओं का सामना करती हैं, जिससे उनकी स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है।

### साहित्य समीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित शैक्षिक एवं सामाजिक असमानताओं के अध्ययन की परंपरा भारतीय समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में लंबे समय से रही है। इस संदर्भ में अरूणा, एन. एस. (1981) का शोध विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक समर्थन जैसे तत्व शिक्षा में असमानता को गहराई से प्रभावित करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से लैंगिक असमानता को भी बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जॉन डब्ल्यू. बेस्ट (1973) की कृति "रिसर्च इन एजुकेशन" अनुसंधान पद्धति के क्षेत्र में एक आधारभूत ग्रंथ के रूप में स्थापित है, जो यह स्पष्ट करती है कि सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण आवश्यक है। इन प्रारंभिक अध्ययनों ने यह आधार प्रदान किया कि अनुसूचित वर्गों में असमानताओं को समझने के लिए केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि शैक्षिक एवं संरचनात्मक कारकों का भी समुचित विश्लेषण किया जाना चाहिए।

आधुनिक संदर्भ में लैंगिक असमानता को एक व्यापक सामाजिक समस्या के रूप में देखा गया है, जिसमें जाति, वर्ग एवं लिंग के अंतर्संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंध्रेव, सुनीता (2010) के अध्ययन में अनुसूचित जाति समाज में लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों को रेखांकित किया गया है, जहाँ महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार गुप्ता, आदित्य (2015) ने जाति और लैंगिक असमानता के संबंध को विश्लेषित करते हुए यह बताया कि सामाजिक संरचना में निहित भेदभाव महिलाओं की स्थिति को और अधिक कमजोर बनाता है। ब्रेन, निकोलस (2008) ने अपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में यह प्रतिपादित किया कि लैंगिक असमानता केवल एक सामाजिक घटना नहीं, बल्कि शक्ति संबंधों और संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम है। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित समुदायों में लैंगिक असमानता बहुस्तरीय है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी तत्व सम्मिलित होते हैं।

अनुसूचित जनजाति समाज के विशेष संदर्भ में लैंगिक असमानता पर किए गए अध्ययनों में यह पाया गया है कि पारंपरिक मान्यताएँ एवं आर्थिक सीमाएँ महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती हैं। देवी, सीमा के विश्लेषण में यह स्पष्ट किया गया है कि जनजातीय समाज को भले ही अपेक्षाकृत समानतावादी माना जाता हो, किंतु वास्तविकता में महिलाओं को संसाधनों, शिक्षा एवं निर्णय-निर्माण में सीमित अवसर प्राप्त होते हैं। शर्मा, संजीव (2020) ने अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि गरीबी, अशिक्षा एवं सामाजिक परंपराएँ इस असमानता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त, जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं के सीमित प्रभाव और संसाधनों की कमी भी महिलाओं की प्रगति में बाधक बनती है। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय समाज में लैंगिक असमानता की प्रकृति जटिल एवं बहुआयामी है, जिसे केवल एक कारक के आधार पर नहीं समझा जा सकता।

हाल के अध्ययनों में परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो यह दर्शाते हैं कि समय के साथ जनजातीय समाज में लैंगिक संबंधों में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यादव, राजेश (2022) के अध्ययन में यह बताया गया है कि शिक्षा, सरकारी योजनाओं एवं जागरूकता अभियानों के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि यह परिवर्तन अभी भी असमान एवं सीमित है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs), महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों ने महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान दिया है। फिर भी, पारंपरिक मान्यताओं और संरचनात्मक बाधाओं के कारण यह परिवर्तन पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया है। समग्र रूप से, उपलब्ध साहित्य यह संकेत करता है कि अनुसूचित जनजाति समाज में लैंगिक असमानता एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें परंपरा और परिवर्तन दोनों का प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः इस विषय पर और अधिक गहन एवं क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता बनी हुई है, जिससे नीति-निर्माण एवं सामाजिक हस्तक्षेप को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

## **सामाजिक कारकों के संदर्भ में लैंगिक असमानता**

### **1. शिक्षा में लैंगिक अंतर**

जनजातीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक अंतर एक प्रमुख सामाजिक समस्या के रूप में उभरता है, जहाँ बालिकाओं की शिक्षा को अक्सर प्राथमिकता नहीं दी जाती। आर्थिक सीमाएँ, घरेलू कार्यों का बोझ

तथा पारंपरिक धारणाएँ लड़कियों की शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता दर एवं उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी कम रहती है।

## **2. स्वास्थ्य एवं पोषण में असमानता**

स्वास्थ्य एवं पोषण के संदर्भ में भी महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधनों की स्थिति में परिवार में पुरुषों और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की उपेक्षा होती है। कुपोषण, मातृ मृत्यु दर एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच इस असमानता को और गहरा करती है।

## **3. विवाह एवं पारिवारिक संरचना**

जनजातीय समाज में विवाह एवं पारिवारिक संरचना लैंगिक संबंधों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विवाह की परंपराएँ, जैसे प्रारंभिक विवाह या वधू मूल्य, महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती हैं। पारिवारिक संरचना में प्रायः पुरुष प्रधानता देखी जाती है, जहाँ निर्णय लेने का अधिकार मुख्यतः पुरुषों के पास होता है, जबकि महिलाओं की भूमिका घरेलू दायित्वों तक सीमित रहती है।

## **4. सामाजिक मान्यताएँ एवं परंपराएँ**

सामाजिक मान्यताएँ और परंपराएँ लैंगिक असमानता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जनजातीय समाज में प्रचलित रीति-रिवाज, सांस्कृतिक धारणाएँ एवं परंपरागत मूल्य महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसरों को सीमित करते हैं। ये मान्यताएँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, जिससे असमानता का निरंतर पुनरुत्पादन होता रहता है।

## **5. निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भूमिका**

निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। चाहे वह परिवार का स्तर हो या समुदाय का, महत्वपूर्ण निर्णय प्रायः पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। हालांकि, शिक्षा, जागरूकता एवं सरकारी प्रयासों के कारण कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी जा रही है, फिर भी यह परिवर्तन अभी सीमित और असमान है।

उपरोक्त सामाजिक कारकों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनजातीय समाज में लैंगिक असमानता बहुआयामी एवं संरचनात्मक प्रकृति की है, जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से निरंतर बनी रहती है और परिवर्तन के बावजूद पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

## **आर्थिक कारकों के संदर्भ में लैंगिक असमानता**

### **1. रोजगार एवं आजीविका के अवसर**

जनजातीय समाज में महिलाओं के लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसर सीमित और अस्थिर होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। महिलाएँ प्रायः कृषि, वनोपज संग्रहण तथा दिहाड़ी मजदूरी जैसे निम्न आय वाले कार्यों में संलग्न रहती हैं, जबकि औपचारिक एवं स्थायी रोजगार के अवसरों में उनकी भागीदारी कम होती है। कौशल विकास एवं शिक्षा की कमी भी इस असमानता को बढ़ाती है।

### **2. आय एवं संपत्ति पर अधिकार**

आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण पहलू आय एवं संपत्ति पर अधिकार से जुड़ा है, जहाँ महिलाओं की पहुँच सीमित पाई जाती है। अधिकांश मामलों में भूमि, घर तथा अन्य संसाधनों का स्वामित्व पुरुषों

के नाम पर होता है, जिससे महिलाएँ आर्थिक निर्णयों में निर्भर बनी रहती हैं। इससे उनकी सामाजिक स्थिति और सशक्तिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

### **3. श्रम विभाजन एवं असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति**

जनजातीय समाज में श्रम का विभाजन लैंगिक आधार पर निर्धारित होता है, जहाँ महिलाओं को घरेलू कार्यों के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भी भाग लेना पड़ता है। इसके बावजूद उनके कार्य को अक्सर मान्यता नहीं मिलती और उन्हें कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है। अधिकांश महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होती हैं, जहाँ श्रम सुरक्षा, वेतन स्थिरता एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है।

### **4. गरीबी एवं लैंगिक असमानता का संबंध**

गरीबी और लैंगिक असमानता के बीच गहरा अंतर्संबंध पाया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के संसाधनों में कम प्राथमिकता मिलती है, जिससे उनकी स्थिति और कमजोर हो जाती है। यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिससे लैंगिक असमानता का स्थायीकरण होता है।

### **5. सरकारी योजनाओं एवं आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों का प्रभाव**

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ, जैसे स्वयं सहायता समूह (SHGs), कौशल विकास कार्यक्रम एवं महिला सशक्तिकरण योजनाएँ, जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करती हैं। इन पहलों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, वित्तीय सहायता एवं उद्यमिता के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि, इन योजनाओं का प्रभाव क्षेत्र, जागरूकता एवं क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जिसके कारण इनका लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता।

इस प्रकार, आर्थिक कारकों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जनजातीय समाज में लैंगिक असमानता केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि गहराई से आर्थिक संरचनाओं में भी निहित है, जिसे दूर करने के लिए समग्र एवं प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक है।

### **लैंगिक असमानता में परिवर्तन के कारक**

#### **1. शिक्षा एवं जागरूकता का प्रभाव**

शिक्षा एवं जागरूकता लैंगिक असमानता को कम करने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक हैं, क्योंकि ये महिलाओं को ज्ञान, आत्मविश्वास और अधिकारों के प्रति सचेत बनाते हैं। जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रसार से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, जिससे वे पारंपरिक बंधनों से बाहर निकलकर निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

#### **2. शहरीकरण एवं आधुनिकीकरण**

शहरीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं ने जनजातीय समाज की पारंपरिक संरचनाओं को प्रभावित करते हुए लैंगिक संबंधों में परिवर्तन लाया है। रोजगार के नए अवसर, शिक्षा की उपलब्धता तथा बाहरी समाज के साथ संपर्क बढ़ने से महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। हालांकि, यह परिवर्तन सभी क्षेत्रों में समान नहीं है और कुछ मामलों में पारंपरिक मूल्यों एवं आधुनिक विचारों के बीच संघर्ष भी उत्पन्न होता है।

#### **3. सरकारी नीतियाँ एवं योजनाएँ**

सरकार द्वारा संचालित विभिन्न नीतियाँ एवं योजनाएँ, जैसे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, शिक्षा योजनाएँ, तथा स्वरोजगार योजनाएँ, लैंगिक असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक सहायता, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि इनके प्रभाव का स्तर कार्यान्वयन की गुणवत्ता और पहुँच पर निर्भर करता है।

#### **4. गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका**

गैर-सरकारी संगठन जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार जागरूकता, तथा कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच और सामूहिक शक्ति का अनुभव भी प्राप्त होता है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आता है।

#### **5. मीडिया एवं संचार माध्यमों का प्रभाव**

मीडिया एवं संचार माध्यमों ने लैंगिक असमानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को नए विचार, अवसर एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे पारंपरिक धारणाओं में बदलाव आ रहा है और महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण धीरे-धीरे सकारात्मक हो रहा है।

समग्र रूप से, ये सभी कारक जनजातीय समाज में लैंगिक असमानता के स्वरूप को परिवर्तित करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, हालांकि इनका प्रभाव क्षेत्रीय, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में परिलक्षित होता है।

#### **निष्कर्ष**

अनुसूचित जनजाति समाज में लैंगिक असमानता का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यह समस्या बहुआयामी एवं संरचनात्मक प्रकृति की है, जो सामाजिक एवं आर्थिक दोनों कारकों के अंतर्संबंध से उत्पन्न होती है। यद्यपि जनजातीय समाज को प्रायः समानतावादी माना जाता है, तथापि वास्तविकता में महिलाओं की स्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संपत्ति अधिकार तथा निर्णय-निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कमजोर पाई जाती है। सामाजिक मान्यताएँ, पारंपरिक भूमिकाएँ एवं सांस्कृतिक धारणाएँ महिलाओं के अवसरों को सीमित करती हैं, जबकि आर्थिक संसाधनों पर सीमित नियंत्रण, असंगठित क्षेत्र में कार्य तथा गरीबी उनकी निर्भरता को बढ़ाते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोणों—जैसे नारीवादी सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत एवं अंतर्विभाजन—के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि लैंगिक असमानता केवल एक अलग-थलग समस्या नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संरचनाओं और शक्ति संबंधों से जुड़ी हुई है। हालांकि, शिक्षा, जागरूकता, शहरीकरण, सरकारी नीतियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों के कारण जनजातीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाएँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण की पहल तथा सामाजिक चेतना के विस्तार ने असमानता को कम करने की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं, फिर भी यह परिवर्तन अभी आंशिक और असमान है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय संदर्भों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण तथा महिलाओं की शिक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस

प्रकार, समग्र एवं समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर ही अनुसूचित जनजाति समाज में लैंगिक समानता स्थापित की जा सकती है और सतत सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

### सन्दर्भ

1. अरूणा, एन. एस. (1981). 'ए स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अचीवमेंट ऑफ सेविन्थ स्टैंडर्ड बिलॉन्गिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स'. पीएचडी थेसिस, शिक्षा विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय।
2. बेस्ट, जॉन डब्ल्यू. (1973). "रिसर्च इन एजुकेशन" (तृतीय संस्करण). प्रिंटिंग हॉल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. आंध्रव, सुनीता. (2010). 'अनुसूचित जाति और समाज में लैंगिक असमानता: एक अध्ययन'. समाजशास्त्र पत्रिका, विकास प्रकाशन, मुंबई, पृष्ठ 45-60।
4. देवी, सीमा. (वर्ष अज्ञात). 'लैंगिक असमानता और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति: एक विश्लेषण'।
5. गुप्ता, आदित्य. (2015). 'जाति और लैंगिक असमानता के प्राथमिक अध्ययन'. जातिवादी दृष्टिकोण, भारतीय विश्वविद्यालय प्रेस, कोलकाता, पृष्ठ 115-130।
6. शर्मा, संजीव. (2020). 'अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और लैंगिक असमानता: एक विश्लेषण'. समाजशास्त्र अनुसंधान, राजाराम प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ 75-90।
7. ब्रेन, निकोलस. (2008). 'जाति, लैंगिक और सामाजिक असमानता: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य'. विकास और उद्यमिता संघर्ष और संभावनाएँ, नई दिल्ली, पृष्ठ 72-89।
8. यादव, राजेश. (2022). 'अनुसूचित जनजातियों में लैंगिक असमानता: एक विश्लेषण'. समाजवादी चुनौतियाँ, प्रज्ञा प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ 65-80।
9. सिंह, नितिन. (2021). 'अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लैंगिक असमानता: एक मुख्य चुनौती'. समाजशास्त्र अनुसंधान, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ 45-60।
10. मिश्रा, आशीष. (2017). 'लैंगिक असमानता और अनुसूचित जनजातियों का समाज: एक अध्ययन'. जागकता, विश्वविद्यालय प्रकाशन, लखनऊ, पृष्ठ 25-40।
11. गांधी, मोहन. (2022). 'लैंगिक असमानता और अनुसूचित जनजाति: समाजशास्त्रीय विश्लेषण'. जातिवाद और समाज, विकास प्रकाशन, अहमदाबाद, पृष्ठ 60-75।